शनिवार, 20 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

वैभव सूर्यवंशी को श्रीकांत ने बताया भारतीय क्रिकेट का भविष्य

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

ग्लैमर, प्यार और जलन का मिश्रण,अधूरा रह गया 'कॉकटेल 2' का स्वाद

Page-05

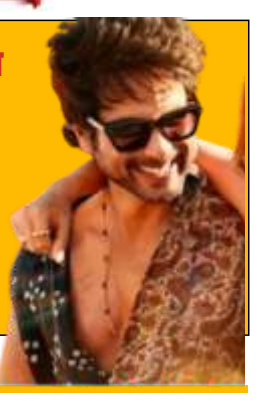

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बयानबाजी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।ट्रंप के एक बयान पर मेलोनी ने कड़ा जवाब देते हुए कूटनीतिक मर्यादाओं की बात कही।विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का असर वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।

बयानों से बढ़ी सियासी गर्मी

ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी के बीच जुबानी जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच हाल ही में हुई बयानबाजी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से हुई टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं को वैश्विक मीडिया प्रमुखता से उठा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शीर्ष नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी न केवल घरेलू राजनीति बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर भी प्रभाव डाल सकती है।विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेहद उत्साहित थीं और उन्होंने इस मुलाकात को विशेष महत्व दिया। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कई पर्यवेक्षकों ने इसे एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी माना, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे एक सहयोगी देश के नेता के प्रति असामान्य बयान बताया।ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने परोक्ष रूप से कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को व्यक्तिगत प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। मेलोनी ने कहा कि वैश्विक नेताओं के बीच संबंध आपसी सम्मान, साझा हितों और सहयोग की भावना पर आधारित होने चाहिए, न कि व्यक्तिगत दावों और राजनीतिक बयानबाजी पर। उनके इस बयान को ट्रंप की टिप्पणी का सीधा प्रतिवाद माना जा रहा है।राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब पश्चिमी देशों के सामने कई गंभीर वैश्विक चुनौतियां मौजूद हैं। यूक्रेन संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाएं, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच निरंतर संवाद चल रहा है। ऐसे में प्रमुख नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और इटली के द्विपक्षीय संबंध मजबूत और दीर्घकालिक हैं। दोनों देश नाटो सहयोगी होने के साथ-साथ रक्षा, व्यापार और रणनीतिक मामलों में करीबी साझेदार हैं। इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियों से संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। इसके बावजूद ट्रंप और मेलोनी के बीच हुई यह जुबानी जंग अंतरराष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है।

- ट्रंप के बयान पर मेलोनी का तीखा पलटवार, कूटनीतिक शिष्टाचार पर जोर।
- अमेरिका-इटली संबंधों पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं, लेकिन वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज।

फ्रांस दौरा सफल, रक्षा, एआई और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी उपलब्धियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया फ्रांस दौरा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत तकनीकों से जुड़े कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।दौरे के दौरान रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा रहा। दोनों देशों ने राफेल लड़ाकू विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी मजबूत करने पर सहमति बनी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी।कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। एआई आधारित तकनीकों, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय और फ्रांसीसी एजेंसियों के बीच नए समझौतों से उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और डेटा साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद है।

टीएमसी का हमला, लोकसभा स्पीकर को सौंपीं 20 अयोग्यता याचिकाएं

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपने बागी सांसदों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को 20 अयोग्यता याचिकाएं सौंप दी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि संबंधित सांसदों ने जनता के जनादेश और पार्टी के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को पार्टी के टिकट और संगठन के समर्थन के आधार पर जनता ने चुना, वे अब व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक ताकतों के साथ खड़े हो गए हैं।अभिषेक बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में दल-बदल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सांसदों ने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी "ईमानदारी बेच दी" और जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान किया। टीएमसी का कहना है कि संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।सूत्रों के अनुसार, लोकसभा सचिवालय ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और अब इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संसदीय नियमों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष को संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि याचिकाएं स्वीकार हो जाती हैं तो संबंधित सांसदों की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है।विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ दलों का कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि को राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि अन्य दलों ने टीएमसी के कदम को उचित बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल संसदीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजरें लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी हुई हैं।

ईरान पर ट्रंप का सख्त रुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में दिए गए एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता पहले की तुलना में काफी कमजोर हो चुकी है और अमेरिका अब तेहरान को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराएगा। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से ईरान की नीतियों को लेकर चिंतित रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है और इसलिए अमेरिका को उसके प्रति कठोर नीति अपनानी पड़ रही है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ईरान के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक रियायत देने के पक्ष में नहीं है।विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान पश्चिम एशिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आया है। क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ईरान, इजरायल तथा अमेरिका के बीच संबंध लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान क्षेत्रीय राजनीति को और प्रभावित कर सकता है।ईरान की ओर से हालांकि ट्रंप के बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लगातार दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील करती रही हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को देखते हुए भी ट्रंप के ऐसे बयान घरेलू राजनीति से जुड़े संदेश के रूप में देखे जा सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।

खावड़ा परियोजना से भारत को मिलेगी नई ऊर्जा, अदाणी समूह का बड़ा लक्ष्य

गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खावड़ा क्षेत्र में विकसित किया जा रहा विशाल नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भारत की ऊर्जा क्रांति का नया प्रतीक बनता जा रहा है। अदाणी समूह ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह परियोजना पूरी होने पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन सकती है।खावड़ा परियोजना में सौर और पवन ऊर्जा दोनों का उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी बड़ी क्षमता का ऊर्जा पार्क भारत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में पहुंचा सकता है। सरकार भी वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विशेष महत्व दे रही है।अदाणी समूह का कहना है कि इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति मिलेगी। कंपनी के अनुसार, अत्याधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हालांकि कुछ पर्यावरणविदों ने इतनी विशाल परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

टेलीग्राम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को दी मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG पेपर लीक और बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंधों को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग यदि गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो सरकार को सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और इसका दुरुपयोग रोकना भी उतना ही आवश्यक है।मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि हाल के वर्षों में कई परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने, साइबर ठगी, फर्जी निवेश योजनाओं और आपराधिक गतिविधियों के संचालन में टेलीग्राम के कुछ चैनलों और समूहों का इस्तेमाल किया गया। विशेष रूप से NEET-UG परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में भी टेलीग्राम के कई चैनलों की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया।याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि किसी एक मंच का दुरुपयोग होने के कारण पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उनका कहना था कि लाखों छात्र, शिक्षक और व्यवसायी टेलीग्राम का उपयोग शैक्षणिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। हालांकि, अदालत ने माना कि यदि किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही हो, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को उचित ठहराया जा सकता है।

गाजा में पहचान का संकट गहराया

मलबे में दबे हजारों लोगों का सुराग मिलना मुश्किल

लगातार महीनों तक चले संघर्ष ने गाजा में अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा कर दिया है। युद्धविराम के बावजूद हजारों लोग अब भी लापता हैं और बड़ी संख्या में शव मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस ने चेतावनी दी है कि पर्याप्त संसाधन न मिलने पर कई पीड़ितों की पहचान हमेशा के लिए अधूरी रह सकती है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

युद्धविराम और राहत प्रयासों के बावजूद गाजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) ने चेतावनी दी है कि संघर्ष के दौरान ढही इमारतों और मलबे के नीचे दबे हजारों लोगों की पहचान भविष्य में संभवतः कभी नहीं हो पाएगी। संगठन का कहना है कि समय बीतने के साथ स्थिति और जटिल होती जा रही है तथा यदि तत्काल बड़े पैमाने पर तकनीकी और मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई गई तो अनेक परिवार अपने प्रियजनों के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे।राहत एजेंसियों के अनुसार गाजा के कई हिस्सों में अब भी भारी मात्रा में मलबा जमा है। सीमित संसाधनों और क्षतिग्रस्त मशीनरी के कारण खोज अभियान अपेक्षित गति से नहीं चल पा रहा है। स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवक साधारण उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर खोज कार्य के लिए आधुनिक तकनीक और विशेष उपकरणों की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय बीतने के साथ शवों की पहचान करना लगातार कठिन होता जा रहा है।आईसीआरसी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि खोज, पहचान और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। संगठन का मानना है कि मृतकों की पहचान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि उनके प्रियजन जीवित हैं या नहीं।गाजा में बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान ने संकट को और गंभीर बना दिया है। कई अस्पताल, प्रयोगशालाएं और सरकारी संस्थान पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। डीएनए परीक्षण, रिकॉर्ड संकलन और पहचान से जुड़ी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि केवल युद्धविराम से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली और संस्थागत सहयोग भी आवश्यक है।मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून से जुड़ा विषय बताया है। उनका कहना है कि प्रत्येक परिवार को अपने लापता परिजन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। विशेषज्ञों के अनुसार गाजा की वर्तमान स्थिति युद्ध के दीर्घकालिक मानवीय प्रभावों का एक गंभीर उदाहरण है। हजारों परिवार आज भी अनिश्चितता और प्रतीक्षा के बीच जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में राहत एजेंसियां खोज, पहचान और पुनर्वास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को न्याय, सम्मान और मानसिक राहत मिल सके।

जी-7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर जोर

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया गया। नेताओं ने माना कि नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर खतरों और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इस दिशा में साझा मानकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर बल दिया गया।आर्थिक मोर्चे पर सदस्य देशों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की आवश्यकता बताई। हाल के वर्षों में विभिन्न संघर्षों, महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसे में जी-7 देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की।जलवायु परिवर्तन भी सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल रहा। सदस्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।विशेषज्ञों का मानना है कि जी-7 के निर्णयों का प्रभाव केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर भी पड़ता है। इसलिए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों और जारी किए गए वक्तव्यों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय गंभीरता से देख रहा है। कुल मिलाकर एवियां शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल बहुपक्षीय सहयोग और संवाद के माध्यम से ही संभव है।

पुलवामा जिले में 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने पूजा-अर्चना की

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने पूजा-अर्चना की है। शुक्रवार को मुरान इलाके में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने देवी की पूजा की। स्थानीय मुसलमानों ने पूजा में शामिल होने वाले कश्मीरी पंडितों का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह इलाका कभी हिंसा, पत्थरबाजी और आतंकवाद की खबरों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहां हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला नजारा देखने को मिला। देश भर के अलग-अलग राज्यों से आए कश्मीरी पंडित देवी की श्रद्धा में पूजा और हवन करने के लिए इकट्ठा हुए। इस मौके पर कश्मीरी पंडित बहुत भावुक हो गए और उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही उनकी घर वापसी के लिए ठोस कदम उठाएगी। स्थानीय कश्मीरी मुसलमान उन पंडितों के साथ एकजुटता से खड़े रहे, जो 36 साल बाद अपने गाँव लौटे थे और उन्हें हमेशा के लिए कश्मीर वापस आने का न्योता दिया। 'ब्रारी माएज' के नाम से जाना जाने वाला यह ऐतिहासिक मंदिर कभी कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का एक पवित्र केंद्र था, लेकिन 1989 में आतंकवाद शुरू होने के बाद पंडितों को वहां से भागना पड़ा और मंदिर खंडहर हो गया। हाल ही में हालात में सुधार के साथ, ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और कश्मीरी पंडित फिर से बड़ी संख्या में वहां जा रहे हैं। सिर्फ दस दिनों में, 1,500 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने इन ऐतिहासिक मंदिरों को देखने और धार्मिक उत्सवों में शामिल होने के लिए कश्मीर का दौरा किया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि कश्मीर में हालात अब सामान्य हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात में सुधार आया है। यहां 200 से ज्यादा ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, जो 1990 के दशक में खंडहर हो गए थे। कश्मीरी पंडित अब पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में इन जगहों पर जाते हैं।

फ्रांस ने ईरान परमाणु समझौते पर रखी कड़ी शर्तें यूरोप की भूमिका हुई अहम

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फ्रांस का रुख ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उम्मीदें पैदा हुई हैं। पेरिस का मानना है कि किसी भी समझौते में केवल परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए एक संतुलित और व्यापक समझौता आवश्यक है।ब्रिटेन और जर्मनी ने भी संकेत दिए हैं कि वे किसी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें निगरानी तंत्र पर्याप्त मजबूत न हो। यूरोपीय देशों का तर्क है कि अतीत के अनुभवों को देखते हुए भविष्य की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। इसी कारण यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश वार्ता प्रक्रिया पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फ्रांस की यह स्थिति केवल सुरक्षा चिंताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यूरोप की कूटनीतिक भूमिका को भी मजबूत करने का प्रयास है। यूक्रेन संकट, मध्य पूर्व तनाव और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के बीच यूरोप अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखना चाहता है।आने वाले दिनों में यदि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो यूरोपीय देशों की सहमति और समर्थन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए फ्रांस द्वारा रखी गई शर्तों को भविष्य की वार्ताओं में एक अहम कारक माना जा रहा है। फिलहाल सभी पक्ष किसी ऐसे समाधान की तलाश में हैं जो सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया पर संकट के बादल, स्विट्जरलैंड वार्ता स्थगित होने से बढ़ी चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मध्य पूर्व में तीन महीने से अधिक समय तक चले संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति प्रक्रिया को ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा था, उस पर अब अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित उच्चस्तरीय वार्ता को अचानक स्थगित कर दिया गया, जिससे स्थायी युद्धविराम और व्यापक समझौते की संभावनाओं को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच पहले एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, जिसके तहत 60 दिनों के भीतर परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक समझौता तैयार किया जाना था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम समय में इसे टाल दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है, जबकि ईरान ने समझौते के कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर संतोषजनक प्रगति की आवश्यकता बताई है।विशेषज्ञों का कहना है कि युद्धविराम की घोषणा के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में राहत का माहौल बना था और तेल कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई थी।

हालांकि वार्ता स्थगित होने से निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच फिर से चिंता बढ़ गई है। मध्य पूर्व के कई देशों ने दोनों पक्षों से संवाद जारी रखने और तनाव कम करने की अपील की है।इस बीच लेबनान सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी झड़पों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि जब तक क्षेत्रीय मोर्चों पर स्थिरता नहीं आती, तब तक अमेरिका-ईरान समझौते को पूरी तरह लागू करना आसान नहीं होगा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार वार्ता स्थगित होने के पीछे कई तकनीकी और राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु गतिविधियों की निगरानी, अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था और प्रतिबंधों में राहत के स्वरूप को लेकर मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अधिक पारदर्शिता दिखाए, जबकि ईरान का कहना है कि प्रतिबंधों में वास्तविक राहत के बिना किसी नए समझौते को स्वीकार करना कठिन होगा।

संपादक की कलम से

भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यह जनसांख्यिकीय शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो यही युवा शक्ति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। लेकिन यदि यह क्षमता सही दिशा नहीं पाती, तो यह सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है।

हाल ही में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। यह स्वागतयोग्य पहल है क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ी जरूरत केवल रोजगार उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि ऐसे रोजगार सृजित करने की है जो बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप हों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों के बढ़ते प्रभाव के बीच पारंपरिक कौशल पर्याप्त नहीं रह गए हैं।

भारत में हर वर्ष लाखों युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। ऐसे में केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहना व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों और बाजार की जरूरतों से जोड़ा जाए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को वास्तविक रोजगार मिल सके।

राज्यों की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य की आर्थिक संरचना, संसाधन और आवश्यकताएं अलग हैं। इसलिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं में राज्यों को अधिक लचीलापन और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयास ही इस लक्ष्य को सफल बना सकते हैं।

इसके साथ ही शिक्षा प्रणाली में भी सुधार आवश्यक है। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल डिग्री आधारित शिक्षा के बजाय कौशल आधारित प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाने की दिशा में भी प्रयास बढ़ाने होंगे।

विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा आत्मनिर्भर, कुशल और आर्थिक रूप से सशक्त बने। रोजगार और कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि भारत के भविष्य में निवेश है। यही निवेश आने वाले वर्षों में देश की प्रगति की सबसे मजबूत नींव साबित होगा।

चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी:

2029 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम उन्नयन पर जोर

राजनीतिक दृष्टि से भी इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देश में चुनाव सुधारों और मतदान प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। आयोग की इस तैयारी को 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और प्रस्ताव पर होने वाले निर्णय पर राजनीतिक दलों तथा चुनावी विशेषज्ञों की नजर बनी रहेगी।

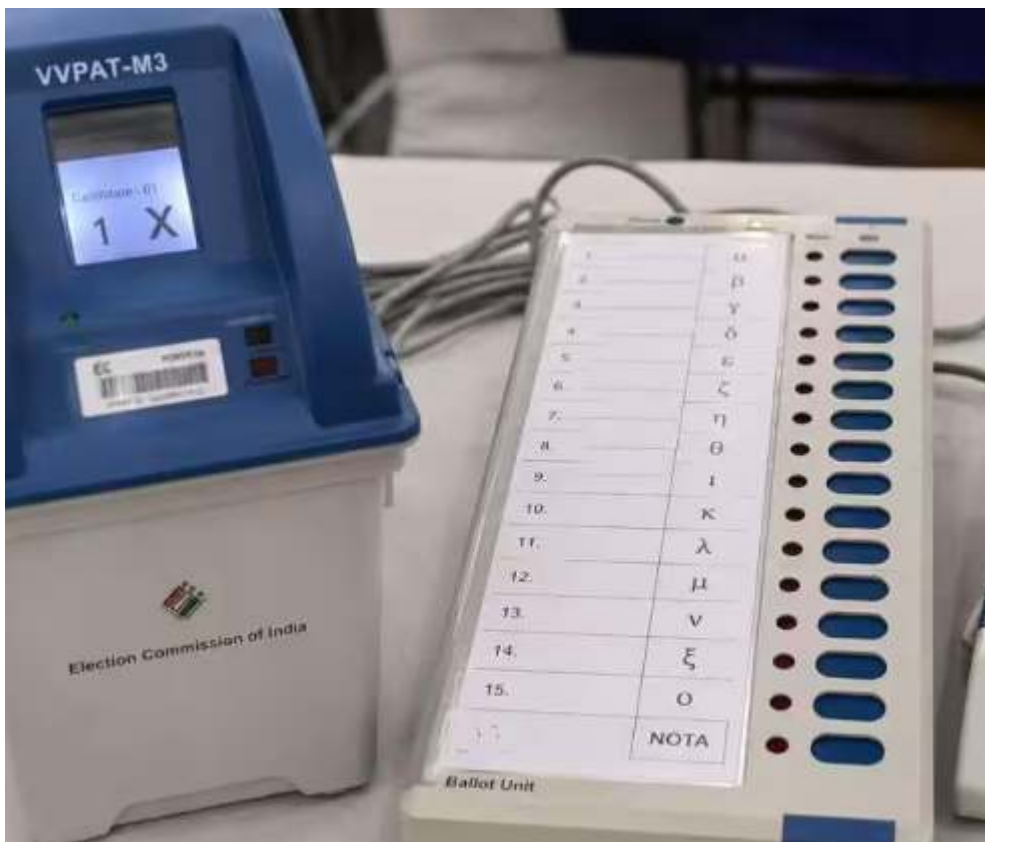

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश में अगले लोकसभा चुनाव भले ही अभी तीन वर्ष दूर हों, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी से तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। आयोग ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वीवीपैट इकाइयों के उन्नयन तथा नई मशीनों की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि की मांग की है। आयोग का मानना है कि आने वाले वर्षों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और नए मतदान केंद्रों की स्थापना के कारण चुनावी संसाधनों की आवश्यकता काफी बढ़ने वाली है।सूत्रों के अनुसार आयोग ने अपनी आंतरिक समीक्षा में पाया है कि वर्तमान में उपयोग की जा रही कई मशीनें अपनी निर्धारित आयु पूरी करने की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में उन्हें समय रहते बदलना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो। आयोग का यह भी मानना है कि मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उपकरणों का नियमित आधुनिकीकरण जरूरी है।आयोग के अनुमान के अनुसार 2029 तक देश में मतदान केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। दूरदराज के क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में नए बूथ स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चुनाव आयोग लंबे समय से यह नीति अपनाता रहा है कि किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अत्यधिक दूरी तय न करनी पड़े। इसी नीति के तहत अतिरिक्त बूथों की स्थापना की जाती है।इसके अलावा देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावनाओं पर चल रही बहस ने भी आयोग की तैयारियों को प्रभावित किया है। यदि भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की मांग वर्तमान से कहीं अधिक हो सकती है। इसी कारण आयोग अभी से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समय-समय पर ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए हैं, हालांकि आयोग लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसके बावजूद आयोग तकनीकी उन्नयन और नियमित परीक्षण की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है ताकि मतदाताओं का विश्वास और मजबूत हो सके।राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग का यह कदम केवल मशीनों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की बढ़ती चुनावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रत्येक चुनाव में करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे में चुनावी ढांचे को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी है।केंद्र सरकार के समक्ष भेजे गए प्रस्ताव में आयोग ने मशीनों की उपलब्धता, रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता से जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख किया है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से नई ईवीएम और वीवीपैट इकाइयों की खरीद की जाएगी। इससे भविष्य के चुनावों में संसाधनों की कमी की आशंका काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, संगठनात्मक मजबूती का मिला संकेत

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणामों ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बढ़त हासिल की, जबकि भाजपा को दो सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव परिणामों को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार दोनों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है।मतदान से पहले राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को लेकर काफी चर्चा थी। कांग्रेस, भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) सभी ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट बनाए रखने के लिए विशेष रणनीति अपनाई थी। परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस अपने विधायकों को संगठित रखने में सफल रही और उसे अपेक्षा से बेहतर समर्थन प्राप्त हुआ।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही थी, उसमें यह परिणाम कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पार्टी नेतृत्व ने

इसे संगठनात्मक एकता और सरकार की नीतियों पर जनता तथा जनप्रतिनिधियों के विश्वास का परिणाम बताया है। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे राज्य सरकार के कामकाज पर लगी मुहर बताया। पार्टी का दावा है कि उसकी जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक मजबूती का लाभ परिषद चुनाव में मिला है। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि परिषद चुनाव के परिणामों को सीधे जनता के जनादेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी पार्टी अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और भविष्य की रणनीति को मजबूत बनाएगी।राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार इस चुनाव का महत्व केवल सात सीटों तक सीमित नहीं है। यह परिणाम आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और राज्य की भावी राजनीतिक दिशा के संकेत भी देता है। विशेष रूप से डी.के. शिवकुमार की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हुई है, क्योंकि चुनाव प्रबंधन और विधायकों के समन्वय में उनकी सक्रिय भागीदारी को सफलता का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन राजनीतिक संदेशों पर रही नजर

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस ने देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में

रक्तदान शिविर, पौधरोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक सेवा कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन कर इस अवसर को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे केवल जन्मदिन का आयोजन न बताते हुए सामाजिक सरोकारों और जनसेवा से जुड़ा अभियान बताया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कई स्थानों पर युवाओं और छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम भी हुए, जिनमें रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की राजनीतिक यात्राओं और विभिन्न जनआंदोलनों में उनकी भूमिका को भी प्रमुखता से रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद नेताओं के इन संदेशों को लोकतांत्रिक परंपराओं और राजनीतिक शिष्टाचार का उदाहरण माना गया। सोशल मीडिया पर भी दिनभर राहुल गांधी से जुड़े संदेश और प्रतिक्रियाएं चर्चा का विषय बनी रहीं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, किसानों की समस्याओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया है। पार्टी ने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हीं विषयों को जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया। कई राज्यों में कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की तथा सामाजिक सहायता से जुड़े अभियान भी चलाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से राजनीतिक दल अपने संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस भी आगामी चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। जन्मदिन के अवसर पर हुए कार्यक्रमों को इसी व्यापक राजनीतिक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा और अन्य दलों ने भी अपने-अपने राजनीतिक अभियानों को जारी रखा। हालांकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा दी गई शुभकामनाओं ने यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैचारिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान और संवाद की परंपरा कायम रहनी चाहिए।

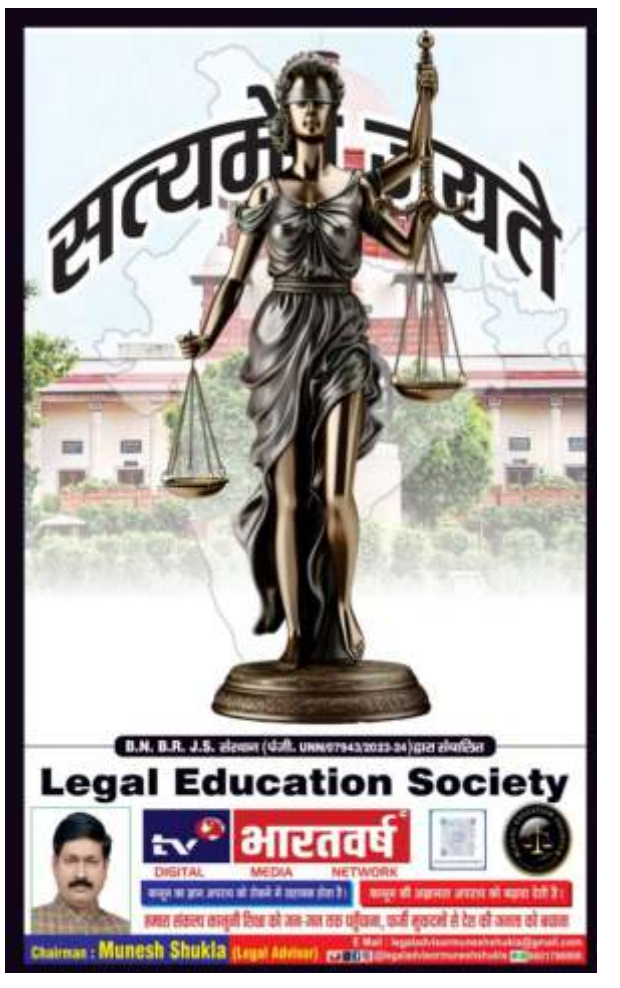

नीट पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार और एनटीए अलर्ट

सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर

21 जून को प्रस्तावित नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को अभ्यर्थियों की सुविधा तथा परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।पिछले महीने पेपर लीक विवाद के बाद नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से सरकार और परीक्षा एजेंसियों पर निष्पक्ष परीक्षा कराने का दबाव बना हुआ है। इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया गया है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को विशेष सतर्कता बरतने तथा आवश्यक होने पर अवकाश सीमित करने के निर्देश दिए हैं।एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए सत्यापित व्हाट्सएप सूचना सेवा भी शुरू की है, जिसके माध्यम से केवल आधिकारिक सूचनाएं ही साझा की जाएंगी। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी संदेशों, कथित पेपर लीक और धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है।विभिन्न राज्यों में परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। कई स्थानों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बिजली, बैठने की व्यवस्था और यातायात प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी के लिए बहुस्तरीय तंत्र तैयार किया गया है। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परिवहन और वितरण से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक प्रत्येक चरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 जैसे आवश्यक प्रशासनिक उपाय भी लागू किए जा सकते हैं।पेपर लीक विवाद के बाद अभ्यर्थियों और अभिभावकों में परीक्षा प्रणाली को लेकर जो चिंताएं उत्पन्न हुई थीं, उन्हें दूर करना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराई जाएगी। एनटीए ने हेल्पलाइन सेवाओं को भी सक्रिय रखा है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल मदद मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पुनर्परीक्षा का महत्व केवल मेडिकल प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। यदि परीक्षा सफलतापूर्वक और विवादों से मुक्त संपन्न होती है तो इससे छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। दूसरी ओर किसी भी प्रकार की अनियमितता सरकार और परीक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकती है।

सीएसआईआर-यूजीसी नेट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर बढ़ी तैयारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG परीक्षा में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. NTA ने परीक्षा की कुल अवधि बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है, जिससे उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए बेहतर समय मिल सकेगा. इसके साथ ही प्रश्न पत्र में रफ वर्क करने के लिए भी ज्यादा जगह उपलब्ध कराई जाएगी. NTA के अनुसार ये बदलाव छात्रों से मिले फीडबैक और परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं. NTA ने बताया है कि NEET UG 2026 परीक्षा की अवधि अब 195 मिनट कर दी गई है. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसमें अटेंडेंस शीट पर साइन करने और परीक्षा से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं का समय भी शामिल रहेगा. NTA का कहना है कि यह बदलाव उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को पेपर हल करने के लिए पठच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए जून 2026 का महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित सीएसआईआर-यूजीसी नेट जून सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 जून को समाप्त हो रही है, जबकि यूजीसी नेट परीक्षा 22 जून से 30 जून तक आयोजित की जाएगी।सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा विज्ञान विषयों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके माध्यम से जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सहायक प्राध्यापक पात्रता निर्धारित की जाती है। देशभर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में प्रवेश तथा शोध अवसरों के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।वहीं यूजीसी नेट परीक्षा भी उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन और शोध के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए प्रमुख परीक्षा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया है और अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तथा प्रवेश पत्रों से जुड़ी सूचनाओं का इंतजार कर रहे हैं।यार्प्त समय मिले और प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से उनका परीक्षा समय प्रभावित न हो. NEET UG 2026 के प्रश्न पत्र में रफ वर्क के लिए भी बदलाव किया गया है. अब उम्मीदवारों को रफ काम, कैलकुलेशन और डायग्राम बनाने के लिए पहले से ज्यादा जगह उपलब्ध कराई जाएगी.पहले रफ वर्क के पेज केवल प्रश्न पत्र के अंत में दिए जाते थे. अब प्रश्न पत्र की शुरुआत में भी रफ वर्क के लिए पेज उपलब्ध होंगे. इससे छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने में मदद मिलेगी. NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर नियमों का पालन करें. एजेंसी के अनुसार ये बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुविधाजनक और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के लिए किए गए हैं.

फॉफ डुप्लेसी ने45 बॉल पर धमाकेदार शतक लगा दिया

फीफा विश्व कप 2026

कई टीमों के लिए 'करो या मरो' की स्थिति

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण में दूसरे दौर के मुकाबले शुरू होने के साथ ही टूर्नामेंट रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। शुक्रवार को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, मोरक्को, ब्राजील, हैती, तुर्किये और पराग्वे जैसी टीमों के बीच महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाने हैं। कई टीमों के लिए यह मैच नॉकआउट दौर की उम्मीदों को जीवित रखने के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं।टूर्नामेंट के पहले दौर में कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिले, जिसके बाद अंक तालिका में स्थिति पहले से अधिक जटिल हो गई है। अमेरिका ने अपने शुरुआती मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था और अब वह लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अगले दौर के करीब पहुंचना चाहेगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगा।स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच होने वाला मुकाबला भी विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोरक्को ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और वह विश्व कप में भी अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगा। वहीं स्कॉटलैंड अपने प्रशंसकों को बड़ी सफलता का तोहफा देने की उम्मीद में है।सबसे अधिक चर्चा ब्राजील और हैती के मुकाबले को लेकर हो रही है। ब्राजील को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन शुरुआती मुकाबले में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं होने के कारण उस पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में टीम इस मैच में दमदार वापसी करना चाहेगी।

वैभव सूर्यवंशी को लेकर बढ़ी चर्चा श्रीकांत ने बताया भारतीय क्रिकेट का भविष्य

भारतीय क्रिकेट में उभरते युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने युवा खिलाड़ी की प्रतिभा की खुलकर सराहना करते हुए कहा है कि उनमें टेस्ट क्रिकेट को नई ऊर्जा देने की क्षमता है। श्रीकांत का मानना है कि इतनी कम उम्र में जिस प्रकार का आत्मविश्वास और आक्रामकता वैभव ने दिखाई है, वह उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा बना सकती है।श्रीकांत ने कहा कि वैभव उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें देखने के लिए दर्शक विशेष रूप से टीवी के सामने बैठते हैं। उन्होंने युवा बल्लेबाज की तुलना भारतीय क्रिकेट की महान परंपरा से जोड़ते हुए कहा कि उनके भीतर असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी युवा खिलाड़ी पर अत्यधिक अपेक्षाओं का दबाव नहीं डालना चाहिए।हाल के महीनों में वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू और आयु वर्ग क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी बल्लेबाजी शैली, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और मैच की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की योग्यता ने क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। इसी कारण उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जाने लगा है। भारतीय क्रिकेट में समय-समय पर कई युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर पहचान बनाई है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है, उसने उन्हें विशेष श्रेणी में ला खड़ा किया है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी तकनीक और आक्रामक मानसिकता उन्हें सीमित ओवरों के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट में भी सफल बना सकती है। यही कारण है कि पूर्व खिलाड़ियों और चयनकर्ताओं की नजर लगातार उनके प्रदर्शन पर बनी हुई है।

एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत

भारत में खेलों के बढ़ते दायरे के बीच एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एशिया के कई देशों के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। आयोजन को भारतीय फेंसिंग के विकास और अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।फेंसिंग भारत में अपेक्षाकृत नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा खेल है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू धरती पर आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता भारतीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करेगी।आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में एशिया के कई प्रमुख देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। विभिन्न वर्गों में होने वाले मुकाबलों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय दल भी घरेलू दर्शकों के सामने बेहतर प्रदर्शन करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। भारतीय फेंसिंग महासंघ के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतियोगिता की मेजबानी देश में फेंसिंग खेल के विकास को नई गति दे सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय खिलाड़ियों को सीखने और अपनी तकनीक सुधारने का अवसर मिलेगा। साथ ही युवा खिलाड़ियों में भी इस खेल के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है।विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में फेंसिंग अभी शुरुआती विकास के चरण में है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। कई भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में घरेलू धरती पर आयोजित यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को और मजबूत कर सकती है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

21 साल से मुफ्त में पानी पिला रहे हैं बुजुर्ग

कहते हैं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वे, जो हर काम के बदले कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं. उनके लिए मेहनत का मतलब रोजी-रोटी, कमाई और जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है. यह गलत भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं. लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए जीते हैं. वे मदद करते हैं, समय देते हैं और अच्छे काम करते हैं, लेकिन बदले में न पहचान चाहते हैं, न तारीफ और न ही कोई इनाम. उनके लिए किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ही सबसे बड़ा पुरस्कार होती है.

ऐसे लोग आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, बस उनकी कहानियां कम सामने आती हैं. राजस्थान से सामने आया एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही इंसानियत की मिसाल पेश करता है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो रहे हैं.

बिहार की बेटी ने किया गजब का कमाल

कभी देखा है साड़ी पहनकर मूनवॉक

माइकल जैक्सन का मशहूर मूनवॉक करना आसान नहीं माना जाता, लेकिन बिहार की एक कंटेंट क्रिएटर ने साड़ी पहनकर ऐसा शानदार परफॉर्मेंस दिया कि सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे भारतीय संस्कृति और पॉप डांस का शानदार मेल बता रहे हैं.

यह वीडियो बिहार की कंटेंट क्रिएटर कोमल कुमारी का है. उन्होंने माइकल जैक्सन के मशहूर गाने 'Billie Jean' पर उनके सिग्नेचर मूनवॉक और कई आइकॉनिक डांस स्टेप्स को साड़ी पहनकर बेहद सहज अंदाज में पेश किया. उनके बैलेंस, फुटवर्क और आत्मविश्वास ने

लोगों का ध्यान खींच लिया. कोमल कुमारी बिहार की एक मल्टी-टैलेंटेड आर्टिस्ट और डिजिटल क्रिएटर हैं. वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @komal__aadya पर मगही भाषा, ट्रेडिशनल लुक, भरतनाट्यम, माइकल जैक्सन ट्रिब्यूट और फनी रील्स शेयर करती हैं. उनके इस अकाउंट पर करीब 85 हजार फॉलोअर्स हैं. वहीं उनके पर्सनल अकाउंट @komalaadya पर भी करीब 16 हजार लोग जुड़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर डांस वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन साड़ी जैसे पारंपरिक परिधान में माइकल जैक्सन का मूनवॉक करना लोगों को अलग लगा.

जब PM मोदी से बोलीं मेलोनी

'हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस'

G7 समिट में दुनिया के बड़े नेता युद्ध, अर्थव्यवस्था पर मंथन कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया की नजर एक अलग ही पल पर टिक गई. दोनों नेताओं के बीच मजेदार बातचीत का वीडियो वायरल है. इंटरनेट पर फिर से #Melodi की चर्चा छिड़ गई है.

दुनिया भर के नेता अहम ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के लिए जुटे हैं. इस बीच वहां औपचारिक बैठकों और पॉलिसी पर चर्चा से इतर एक वीडियो की चर्चा हो रही है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक और मजेदार बातचीत हुई, जिसने

जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई. (फोटो-एएफपी)

सबका ध्यान खींचा.जब नेता समिट में पारंपरिक ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा हुए, तो मेलोनी और पीएम मोदी एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन करते दिखे.

मेलोनी को पीएम मोदी से यह कहते हुए सुना गया, 'आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा.' सोशल मीडिया पर चले Melodi ट्रेंड का जिक्र करते हुए, पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर उनकी लोकप्रियता की ओर इशारा किया. मेलोनी ने तुरंत मजेदार जवाब दिया, 'हां, हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मशहूर हैं.' बता दें कि MELODI जो पीएम मोदी और मेलोनी के सरनेम को मिलाकर बना है. पिछले तीन सालों में एक जाना-माना ऑनलाइन ट्रेंड बन गया है. 2023 में दुबई में COP28 समिट के दौरान मेलोनी की पोस्ट की गई एक सेल्फी ग्लोबल इंटरनेट ट्रेंड बन गई थी.

इटली की नेता ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर की थी और कैप्शन लिखा था, 'COP28 में अच्छे दोस्त #Melodi.' यह हैशटैग वायरल हो गया था. तब से चाहे G7 समिट हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या द्विपक्षीय बैठकें, यह हैशटैग बार-बार सामने आता रहा है. फिर पिछले महीने रोम की यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री ने मेलोनी को 'मेलोडी' (Melody) टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट दिया.

दिल्ली के बारे में गूगल पर क्या सर्च करते हैं पाकिस्तानी?

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है. बंटवारे के बाद बने दोनों देशों के संबंध समय-समय पर तनाव, संघर्ष और राजनीतिक मतभेदों से गुजरते रहे हैं. ऐसे माहौल में दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के बारे में क्या जानना चाहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों जैसी समस्याओं से जूझता रहा है.

ग्लैमर, प्यार और जलन का मिश्रण, अधूरा रह गया 'कॉकटेल 2' का स्वाद

साल 2012 में जब होमी अदजानिया की 'कॉकटेल' आई थी, तो उसने हिंदी सिनेमा में मॉडर्न रिश्तों की एक बिल्कुल नई और बेबाक परिभाषा लिखी थी। सैफ अली खान का बेफिक्रा अंदाज, डायना पेंटी की सादगी और सबसे बढ़कर दीपिका पादुकोण का वो 'वेरोनिका' वाला किरदार, जिसने आज के दौर के अकेलेपन, दिल टूटने के दर्द और अर्बन लाइफस्टाइल को पर्दे पर अमर कर दिया। वह एक ऐसा सिनेमाई ट्रिंक था, जिसका स्वाद आज भी दर्शकों की जुबान पर है। अब पूरे चौदह साल बाद, बॉलीवुड ने उसी पुरानी बोतल में एक नया मिश्रण परोसने की हिम्मत की है। 'कॉकटेल 2' के जरिए मेकर्स एक बार फिर उसी जॉनर में हाथ आजमाने लौटे हैं, जहाँ दो औरतें हैं, एक मर्द है और भावनाओं का वही पुराना उथल-पुथल है। जब शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े चेहरे इस सफर का हिस्सा बनते हैं, तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन क्या यह नया सीक्वल पुरानी फिल्म जैसा नशा छोड़ पाता है, या सिर्फ एक कमज़ोर रीमेक बनकर रह जाता है? आइए इस ताजा कॉकटेल की घूंट-दर-घूंट दास्तां पेश करते हैं। फिल्म की कहानी हमें ले जाती है कुणाल (शाहिद कपूर) और दिया (रश्मिका मंदाना) की दुनिया में। दोनों कोई नए नवेले प्रेमी नहीं हैं, बल्कि पिछले 16 सालों से एक-दूसरे के साथ एक बेहद खूबसूरत और लंबे रिश्ते में बंधे हैं। अपने इसी पुराने प्यार को एक नया मोड़ देने और जिंदगी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए यह कपल इटली के सिसिली में छुट्टियां मनाने का फैसला करता है। कहानी में मोड़ तब आता है, जब सिसिली में उनकी मुलाकात दिया की एक पुरानी दोस्त एली (कृति सेनन) से होती है। दोनों सहेलियां पूरे एक दशक यानी 10 साल बाद मिल रही हैं। अब यहाँ से कहानी एक अजीब और थोड़े अवास्तविक मोड़ पर मुड़ जाती है। दिया को अचानक अपने इतने लंबे और सुरक्षित रिश्ते पर शक होने लगता है। वह एक अजीब सा खेल खेलने की सोचती है और अपनी बेहद ग्लैमरस और हॉट दोस्त एली को काम सौंपती है कि वह कुणाल को लुभाए, ताकि वह कुणाल की वफादारी को परख सके। एली शुरुआत में दिया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है। दिया का यह अजीब रवैया कुणाल को उससे दूर धकेल देता है और जाने-अनजाने में एली के लिए कुणाल के करीब आने का रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद वही होता है जिसकी उम्मीद हर दर्शक को पहले से होती है, एली को सच में कुणाल से प्यार हो जाता है। अब सहेली की शादी बचाने की कोशिश, एक तरफा जलन और अपने प्यार को पाने की जिद के बीच रिश्तों का एक अजीब सा कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है, जहाँ कुणाल महज एक ट्रॉफी की तरह बीच में खड़ा रह जाता है।

अभिनय के मोर्चे पर बात करें तो यह फिल्म पूरी तरह से कृति सेनन के कंधों पर टिकी हुई है। कृति स्क्रीन पर आते ही छा जाती हैं; उनके लुक्स, कपड़े, हेयरस्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस को बहुत ही बारीकी से और बेहद खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। एली के रूप में वे एक 'गोल्डन गर्ल' की तरह चमकती हैं। हालांकि स्क्रिप्ट की कमजोरी की वजह से उनका किरदार थोड़ा सतही लगता है, लेकिन कृति ने अपनी हॉटनेस और ईमानदारी से उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन्स और फुटेज उन्हीं के हिस्से आया है। शाहिद कपूर जैसे मंझे हुए अभिनेता के लिए इस फिल्म में करने को बहुत कम गुंजाइश थी। पूरी फिल्म में उनका किरदार कुणाल, दोनों अभिनेत्रियों के बीच एक इनाम या ट्रॉफी की तरह घूमता रहता है। एक तरफ उनकी मंगेतर उन पर शक कर रही है, तो दूसरी तरफ उनकी दोस्त उन्हें हासिल करना चाहती है। शाहिद को अपने अभिनय की गहराई दिखाने का मौका सिर्फ फिल्म के आखिरी 10-15 मिनट में मिलता है, जहाँ क्लाइमेक्स के दौरान वे एक बेहतरीन एक्टर होने के नाते बाजी मार ले जाते हैं और अपने किरदार को एक ठहराव देते हैं। रश्मिका मंदाना के मामले में फिल्म निराश करती है। उन्हें इस पूरी कहानी में बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। उनके हिस्से न तो अच्छे कपड़े आए और न ही उनके किरदार को कोई मजबूती दी गई। रश्मिका का हिंदी बोलने का लहजा (डिक्शन) कई जगह खटकता है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी फीकी लगती है। उनका किरदार एक ऐसी इनसिक्योर लड़की का बनकर रह गया है जो अपनी सहेली से अपना मर्द बचाने की जद्दोजहद में लगी है, जबकि असल में उसे उस टॉक्सिक दोस्त को अपनी जिंदगी से बहुत पहले ही बाहर कर देना चाहिए था।

राहुल गांधी के जन्मदिन पर अजय राय का रुद्राभिषेक

राममंदिर चढ़ावा मामले पर अजय राय का सरकार पर हमला

राहुल गांधी के जन्मदिन पर अजय राय ने रुद्राभिषेक किया और राममंदिर चढ़ावा मामले की उच्च न्यायालय निगरानी में जांच की मांग करते हुए एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित हनुमंत धाम में रुद्राभिषेक कर उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के राममंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग उठाई। हनुमंत धाम में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अजय राय ने विधि-विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने शिवलिंग पर पंचगव्य अर्पित किया तथा जलाभिषेक कर देश और समाज के कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राममंदिर चढ़ावा मामले में राज्य सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम और भारतीय संस्कृति का सम्मान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राममंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में गंभीर अनियमितताओं की आशंका है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा, "हम रामभक्त हैं, इनकी तरह चंदा चोर और चढ़ावा चोर नहीं हैं। यदि सरकार में थोड़ी भी पारदर्शिता है तो मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जानी चाहिए। "प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अयोध्या प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि मौजूदा जांच प्रक्रिया पर जनता का भरोसा नहीं बन पा रहा है और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जांच आवश्यक है। उन्होंने राज्य सरकार पर विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया।राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए अजय राय ने कहा कि आज केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक राहुल गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने वाला नेता बताते हुए कहा कि वे लगातार संविधान, सामाजिक न्याय और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती के लिए निरंतर आवाज उठाई है। इसी कारण कांग्रेस कार्यकर्ता उनके नेतृत्व को प्रेरणादायी मानते हैं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। हनुमंत धाम में पूजा-अर्चना संपन्न करने के बाद अजय राय कांग्रेस मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 2 बजे उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित जन्मदिन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के साथ-साथ अजय राय के राजनीतिक बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। विशेष रूप से राममंदिर चढ़ावा मामले और उसकी जांच को लेकर दिए गए उनके बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

लखनऊ में गर्मी का सितम, पारा 41 डिग्री के पार

लखनऊ में सुबह से तेज धूप निकली है। दिन में कई बार बादल भी छाए रह सकते हैं। उमस और तपन सुबह से ही परेशान कर रही है। घर के बाहर निकलने में लोग परहेज कर रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा। गुरूवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 59 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 33 फीसदी दर्ज की गई। लखनऊ में मौसम सामान्य बना हुआ है। इस बीच पारा लगातार बढ़ रहा है। गर्म हवा के थपेड़े सुबह से ही चल रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ कि आने वाले दिनों में लखनऊ का अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री अधिक रहेगा। इससे महीने में पारा अपने अधिकतम स्तर पर दर्ज किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में थंडरस्टार्म के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी और छिटपुट बारिश की संभावना के बावजूद आगामी 5 दिनों के दौरान तापमान बढ़ता रहेगा। लू की स्थितियां जारी रहने की संभावना है । फिलहाल, मानसून के यूपी और लखनऊ में आने की परिस्थिति अनुकूल नहीं है।

लाइब्रेरियन भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन

कई जिलों से लखनऊ पहुंचे 50 से ज्यादा युवाओं ने लाइब्रेरियन की वैकेंसी की मांग की। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के मुख्यालय के बाहर आयोग सचिव से मिलने को लेकर अड़े रहे। युवाओं ने कहा कि 2016 से लाइब्रेरियन की कोई भर्ती नहीं हुई। हम लोगों ने डिग्री लेकर करिअर बर्बाद कर लिया। अप्रशिक्षित लोग लाइब्रेरियां चला रहे हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है। हम डिग्री लेकर बेकार घूम रहे हैं। सरकार से मांग की जाती है कि वैकेंसी निकाले। PET-2025 के आधार पर नई वैकेंसी निकालेंगे तो ठीक रहेगा। आगे आने वाले बच्चों को भी लाइब्रेरी साइंस कोर्स करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अन्यथा यह कोर्स ही बंद करा दिया जाए। झांसी से आए संजय जैन ने कहा- यूपी में 2006 में लाइब्रेरी एक्ट बना हुआ था। उसका कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी ऐसे व्यक्तियों से चलवाई जा रही हैं, जो कहीं से भी डिग्री लिए हुए नहीं हैं। वे कुशल भी नहीं हैं। हम लोगों ने जो लाइब्रेरी की डिग्री ली है, वह सब अपना करिअर बर्बाद किया है। हम लोग यह चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान का कोर्स बंद करा दिया जाए या हमारे लिए नई वैकेंसी निकाली जाए। इससे आने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा दिल्ली से आए गौरव राणा ने कहा- PET 2021, 2022, 2025 भी दे दिया लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। यहां हम आते हैं तो सचिव सर से मिलने नहीं दिया जाता। कर्मचारियों से मिलाकर वापस भेज देते हैं। कभी बताते हैं अधियाचन है तो कभी बताते हैं अधियाचन नहीं है। इस तरह से हम दर-दर भटक रहे हैं। मैंने लाइब्रेरियन के कोर्स किए हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन तेज

लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में 18 दिन से जारी छात्रों का धरना आज, शुक्रवार को बड़ा होने वाला है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में महापंचायत बुलाई है। छात्र गेट-1 पर स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। धरना 3 छात्रों के निष्कासन के बाद 2 जून से शुरू हुआ था। 2 जून से लगातार धरना दे रहे स्टूडेंट्स को सपा और कांग्रेस का लगातार समर्थन मिल रहा है। छात्रसंघ के पूर्व पदाधिकारी भी खुलकर निष्काषित छात्रों के समर्थन में हैं। छात्रसंघ के कई पूर्व पदाधिकारी भी धरना स्थल पर आकर छात्रों के साथ धरना दे चुके हैं। वहीं, सपा और कांग्रेस के कई विधायक और सांसद भी छात्रों के धरने में शामिल हुए हैं। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन फिलहाल छात्रों के निष्कासन वापसी को लेकर विचार करता नहीं दिख रहा। वहीं, छात्र निष्कासन वापसी के अलावा बढ़ी हुई फीस वृद्धि वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। प्रिंस प्रकाश ने बताया विश्वविद्यालय प्रशासन अपने अड़ियल रुख पर कायम है। आज छात्र पंचायत कर रहे, इसके आगे सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। पर छात्रों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

लखनऊ एयरपोर्ट पर घटेगी उड़ानों की संख्या

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और विमान ईंधन (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों का असर अब हवाई सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ती परिचालन लागत और कई रूटों पर यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों ने लखनऊ से संचालित कई उड़ानों की फ्रीक्वेंसी घटाने की तैयारी शुरू कर दी है। शुरूआती योजना के तहत गोवा, नवी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना, बेंगलुरू, रांची, देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद और चेन्नई समेत 11 शहरों के लिए उड़ानों की संख्या कम की जा सकती है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण विमान ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही लखनऊ से संचालित कुछ रूटों पर यात्री भार अपेक्षा से कम रहने के कारण एयरलाइंस को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कंपनियां कम मांग वाले रूटों पर उड़ानों की संख्या घटाकर परिचालन लागत कम करने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

NEET अभ्यर्थियों के लिए रेलवे की विशेष तैयारी

NEET परीक्षार्थियों को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा के चलते प्रयागराज, वाराणसी और पूर्वांचल के अन्य जिलों की ओर जाने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने चार स्पेशल ट्रेनों को तैयार रखा है। आवश्यकता पड़ने पर इन ट्रेनों का संचालन तत्काल किया जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे अधिकारियों के अनुसार चारबाग स्टेशन के यार्ड में आठ-आठ कोच वाली 4 विशेष रेक खड़ी कर दी गई हैं। मंडल के परिचालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों की संख्या बढ़ने या नियमित ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में इन ट्रेनों को तुरंत चलाया जाए। फिलहाल, इन ट्रेनों के संचालन के लिए 20 जून की तैयारी की गई है, लेकिन यदि 19 जून को भी अतिरिक्त भीड़ सामने आती है तो इन्हें उसी दिन रवाना किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन ने प्रारंभिक योजना के तहत इन स्पेशल ट्रेनों को प्रयागराज और वाराणसी रूट पर चलाने का निर्णय लिया है। दोनों शहरों में बड़ी संख्या में नीट अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र होने के कारण इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रेलवे का मानना है कि अतिरिक्त ट्रेनें चलने से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को सीट व यात्रा सुविधा बेहतर तरीके से मिल सकेगी। चारबाग स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए अतिरिक्त रेलवे स्टाफ की तैनाती की जा रही है। प्लेटफॉर्म, पूछताछ केंद्र और टिकट काउंटरों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जरूरत पड़ते ही स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लें। रेलवे प्रशासन का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन का अंतिम निर्णय यात्रियों की संख्या और मांग के आधार पर लिया जाएगा। यदि नियमित ट्रेनों में क्षमता से अधिक भीड़ देखने को मिलती है तो चारों विशेष ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। मंडल प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा के दौरान यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है।

ऊगू नगर पंचायत में 30 लाख के मरम्मत कार्य पर घोटाले का आरोप, सभासदों ने मांगी जांच

नगर पंचायत ऊगू में अंत्येष्टि स्थल के मरम्मत कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर स्थानीय सभासदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में वार्ड संख्या-40 के सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंत्येष्टि स्थल के मरम्मत कार्य पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च किए गए। सभासदों का कहना है कि इस राशि से नए निर्माण कार्य का प्रस्ताव था, लेकिन इसके बजाय केवल मरम्मत कार्य कराकर भुगतान कर लिया गया। उन्होंने इसे सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बताया है।सभासदों ने अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त अंत्येष्टि स्थल का मूल निर्माण वर्ष 2015-16 में कराया गया था। उनका आरोप है कि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष ने उसी स्थल पर वर्ष 2023-24 में मरम्मत कार्य कराकर करीब 30 लाख रुपये का भुगतान करा लिया। इस पूरे प्रकरण में अध्यक्ष, ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अंत्येष्टि स्थल की पुरानी बाउंड्री वॉल, जो पहले से ही बनी हुई थी, उसका प्लास्टर उखड़वाकर दोबारा प्लास्टर और पुताई कराई गई। इसके अलावा, जो टीन शेड पूरी तरह सही स्थिति में था, उसे भी हटवा दिया गया। सभासदों का आरोप है कि पुराने निर्माण कार्य को नया दिखाकर भारी वित्तीय अनियमितता की गई है। सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि उच्च अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जाए, जो शिकायतकर्ता सभासदों की उपस्थिति में अंत्येष्टि स्थल का स्थलीय निरीक्षण करे, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग भी की गई है।इस पूरे मामले में अब तक नगर पंचायत प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, स्थानीय लोगों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा बनी हुई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

प्रभावित लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका

उन्नाव में पोनी रोड चौड़ीकरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस संबंध में अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले लगभग 40 से 50 मकान मालिकों को शुक्रवार को नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिसों के बाद प्रभावित लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग पहले ही सड़क किनारे आने वाले मकानों पर लाल निशान लगा चुका था। हालांकि, इसके बाद कार्रवाई में कुछ विलंब हुआ था। अब विभाग ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी लाई जा सके। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता एच.डी. अहिरवार ने बताया कि शुक्रवार को सभी चिह्नित भवन स्वामियों को नोटिस दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के कारण पहले कार्यवाही में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अब विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चौड़ीकरण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

गंगाघाट क्षेत्र में किसान की जमीन से अवैध मिट्टी खनन का आरोप

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में एक किसान ने दबंगों पर उसके खेत से जबरन मिट्टी खोदकर बेचने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान रिंकू ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उसका कहना है कि बिना सूचना के जेसीबी और डंपर लगाकर उसकी करीब सात बीघा जमीन से कई फीट गहरी मिट्टी निकाल ली गई। कलिका मऊ निवासी रिंकू के अनुसार, यह घटना रात करीब 11 बजे हुई। उसे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सुबह करीब छह बजे जब वह खेत पर पहुंचा, तो वहां से मशीनें और डंपर जा चुके थे। रिंकू ने बताया कि रात में लगभग 20 से 25 डंपर मिट्टी भरकर ले जाए गए और दो बड़ी मशीनों से खुदाई की गई। रिंकू ने अर्जुन और सतपाल नामक व्यक्तियों पर उसकी जमीन से लगभग सौ डंपर मिट्टी निकलवाने और उसे बेचने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि करीब सात बीघा खेत में कई स्थानों पर 5 से 10 फीट तक गहरी खुदाई की गई है, जिससे खेत की स्थिति खराब हो गई है। पीड़ित ने बताया कि जब उसने मिट्टी उठाने के बारे में जानकारी मांगी, तो उससे पैसे लेने को कहा गया। रिंकू ने पैसे लेने से इनकार करते हुए अपनी जमीन को पहले जैसी स्थिति में लाने और मेड़ की मरम्मत कराने की मांग की। रिंकू का आरोप है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया। आरोपियों ने उसे दबाव में लेने का प्रयास करते हुए कहा कि "ज्यादा बोलोगे तो इसी में दबवा देंगे।" पीड़ित ने इस धमकी की शिकायत भी अधिकारियों से की है। उसने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, उसने खेत की मेड़ और जमीन को पूर्ववत करने की भी अपील की है।

बांगरमऊ एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेटी जांच

डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी जांच की जिम्मेदारी

उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में साधु मिलन दास हत्याकांड के मुख्य आरोपी और एक लाख रुपए के इनामी बदमाश इसराइल उर्फ इजरायल के पुलिस एनकाउंटर की अब मजिस्ट्रेटी जांच होगी। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जांच की जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को सौंपी है। जांच के दौरान पुलिस मुठभेड़ से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की गहन पड़ताल की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह एनकाउंटर के दौरान हुई घटनाओं, पुलिस कार्रवाई और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करेंगे। जांच में यह देखा जाएगा कि मुठभेड़ किन परिस्थितियों में हुई और पुलिस द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम तथ्यों से कितना मेल खाता है। बांगरमऊ क्षेत्र में 9 जून को साधु मिलन दास की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। पुलिस के अनुसार, इसराइल उर्फ इजरायल अपने साथियों के साथ हत्या की वारदात में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने 15 जून को मुठभेड़ के दौरान इसराइल को मार गिराने का दावा किया था। अब इस कार्रवाई की निष्पक्षता और परिस्थितियों की जांच के लिए मजिस्ट्रेटी जांच कराई जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने बताया कि जांच प्रक्रिया में आम लोगों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास एनकाउंटर से संबंधित कोई तथ्य, जानकारी या साक्ष्य है तो वह जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। प्रशासन की ओर से एनकाउंटर से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 4 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं या उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशासन के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही घटनास्थल और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी समीक्षा की जाएगी। जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी और सामने आए तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।

सरैया-बैराज मार्ग ओवरब्रिज निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार

उन्नाव में सरैया-बैराज मार्ग रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब गति पकड़ेगा। रेलवे ट्रैक के ऊपर गर्डर रखने का काम पहले ही पूरा हो चुका है, और अब नॉन-ट्रैक स्पैन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लखनऊ से आए डिप्टी चीफ इंजीनियर आशीष कुमार वर्मा ने मौके का निरीक्षण कर कार्य का शुभारंभ किया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, नॉन-ट्रैक स्पैन का कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले, रेलवे ट्रैक के ऊपर गर्डर रखने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। उस दौरान अप और डाउन दोनों रेलवे लाइनों पर तीन से चार दिनों का ब्लॉक लिया गया था। वर्तमान में, बैराज मार्ग की ओर नॉन-ट्रैक स्पैन लगाने का काम किया जाएगा। डिप्टी चीफ इंजीनियर आशीष कुमार वर्मा ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस बार स्पैन रखने के लिए केवल एक क्रेन का उपयोग किया जाएगा। रेलवे के एक्सईएन अनिल कुमार ने जानकारी दी कि इस ओवरब्रिज में कुल आठ स्पैन लगाए जाने हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग 43 मीटर है। उन्होंने बताया कि एक दिन में चार स्पैन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे यह कार्य दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

शुक्लागंज में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक , आदर्श नगर में कुत्तों के हमले से पांच लोग घायल

उन्नाव के शुक्लागंज नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आदर्श नगर इलाके में कुत्तों के हमले में पांच लोग घायल हो गए। इन घटनाओं से नगरवासियों में दहशत का माहौल है और वे नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। नगर के कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों के झुंड देखे जा सकते हैं। ये कुत्ते राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका शिकायतों के बावजूद कुत्तों के नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आदर्श नगर में हुए हमले में पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार और रेबीज के इंजेक्शन दिए गए। घायलों में 60 वर्षीय राम शंकर, 8 वर्षीय प्रतीक, 5 वर्षीय कृष्णा और 7 वर्षीय परि शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला किया, जिससे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। बच्चों के हाथ-पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। निवासियों का कहना है कि अब दिन के समय भी लोग गलियों से गुजरने में डरते हैं। रात में स्थिति और भी खराब हो जाती है। घरों के बाहर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों के हमले की घटनाओं से अभिभावकों में लगातार चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। करीब तीन महीने पहले सुभाष नगर इलाके में एक कुत्ते ने एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस समय नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुत्ते को पकड़कर नगर सीमा से दूर छोड़ दिया था।

यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

15 जून से नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दौड़ेंगी डबल डेकर ई-बसें

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहली बार इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें डबल डेकर ई-बसें भी शामिल हैं।15 जून से शुरू होने वाली इस सेवा से नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाते हुए इसे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

नोएडा के लोग भी अब डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों में सफर का मजा ले पाएंगे। 15 जून से ये बसें संचालित होंगी। दरअसल, पहली बार नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है। नोएडा अथॉरिटी और यूपी परिवहन निगम मिलकर इन बसों का संचालन करेंगे। अभी फिलहाल 100 इलेक्ट्रिक बसें और 10 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसें चलने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को बहुत राहत मिली। नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यह तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को दिया गया है। अब ग्रेटर नोएडा के लोग एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट होंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट तक भी यह सभी बसें चलेंगी। अभी फिलहाल 110 बस चलाई जाएंगी। इसके बाद इन बसों की संख्या 500 कर दी जाएगी। सभी सेक्टर और सोसाइटियों को भी इन सिटी बसों से जोड़ा जाएगा। इससे ऑटो और कैब पर लोगों की निर्भरता कम होगी। ये सभी बसें इलेक्ट्रिक हैं, जिससे कि किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। इन बसों का किराया भी 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक रखा गया है। जानकारी के मुताबिक, बसों का न्यूनतम किराया 20 रुपये और अधिकतम किराया 50 रुपये होगा। बस पूरी तरह से एयर कंडीशनर (एसी) है और सुरक्षा की दृष्टि से बस में चार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। नोएडा सेक्टर-90 बस डिपो से इन बसों का संचालन होगा। शुरुआत में ये बसें चार रूटों पर चलेंगी। बॉटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सूरजपुर कलेक्ट्रेट और गाजियाबाद न्यू बस अड्डा रूट से होकर चलेंगी। अधिकारियों ने कहा कि मांग के आधार पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार गौतम बुद्ध नगर को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शहर के लोगों को इलेक्ट्रिक बेसों का तोहफा दिया। तीनों प्राधिकरण को फिलहाल 11-11 सिटी बस दी गई हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दादरी विधायक तेजपाल नागर मौजूद रहे। विधायक ने सीएम योगी का आभार जताया और कहा कि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सोचो ना... कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। लेकिन इसके बाद कभी अयोध्या वासियों को वायु सेवा प्राप्त नहीं हो पाई होगी। हजारों वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित थी। आजादी के बाद भी लगातार अपमानित थी। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।

पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी की बात कही गई थी। गोयल ने कहा कि जनता को विपक्ष के नेता की बातों पर भरोसा नहीं है। गोयल ने पत्रकारों से कहा कि अखिलेश यादव के ट्वीट को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि जिस तरह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को विकास से दूर रखा, वहां अराजकता का माहौल बनाया और भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया... उसे देखते हुए जनता उन्हें एक बार फिर नकार देगी। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन अपने प्रशासनिक कामकाज के रिकॉर्ड के दम पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेगा।यादव के सोशल मीडिया पर यह दावा करने के बाद कि भक्तों के चढ़ावे से करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं, राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। उन्होंने इन गड़बड़ियों को बेहद शर्मनाक और दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था पर सीधा प्रहार बताया। यादव ने न्यायपालिका से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया और मंदिर प्रशासन की शुरुआती सफाई को नाकाफी 40-सेकंड का स्पष्टीकरण और महज जुबानी औपचारिकता करार दिया। उन्होंने ट्रस्टियों की पूरी बैठक बुलाने और सुरक्षा फुटेज के साथ नकद राशि की गिनती का मिलान करने की मांग की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं। महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि ट्रस्ट के सभी वित्तीय फ़ैसलों और लेन-देन का बारीकी से रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हें सामूहिक रूप से संभाला जाता है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

राजनाथ सिंह के रिश्ते के भतीजे की इंदौर में मौत,रोड पर एक वाहन ने टक्कर मार दी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रिश्ते के भतीजे की इंदौर में मौत हो गई। उन्हें रोड पर एक वाहन ने टक्कर मार दी थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह Rajnath Singh के रिश्ते के भाई प्रदीप सिंह के बेटे प्रभात सिंह की हादसे में मौत हो गई। उनके शव को दिल्ली भेज दिया गया है। वहां से प्रभात सिंह के पार्थिव शरीर को वाराणसी ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। खास बात यह है कि प्रभात सिंह अचानक अपनी गाड़ी से उतर गए थे। वे दोबारा कार में बैठने ही जा रहे थे कि तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। महज 10 सेकंड के फासले ने एक युवा जिंदगी छीन ली। इंदौर-देवास रोड पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शिप्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्विस रोड पर तेज रफ्तार बस ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार युवक प्रभात अपनी कार में बैठ रहे थे। जब वे कार के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार आ रही बस ने कार में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महज 10 सेकंड के फासले से प्रभात भी दुर्घटना की चपेट में आ गए। अन्यथा जान बच सकती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रिश्ते में भतीजे थे। हादसे में उनके तीन दोस्त भी घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत कार से बाहर निकाला गया। प्रारंभिक सूचना मिली की मृतक भाजपा से जुड़ा है, तो कई नेता घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वहीं, सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक प्रभात के शव को पोस्टमार्टम (पीएम) के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल भिजवाया। यहां से पोस्टमार्टम के बाद शव दिल्ली भेज दिया गया है। वहां से शव बलिया उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा।

घायल बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे

वाराणसी में शिवपुर थाना क्षेत्र के ऊंदी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने दो लोग गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक, जीएसटी अधिकारी के शिवपुरी स्थित ससुराल में आरोपियों ने करीब ढाई करोड़ की चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक, एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शिवपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर इलाके में जीएसटी अधिकारी के ससुराल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ऊंदी के पास मौजूद हैं। इस सूचना के बाद एसओजी प्रभारी ने शिवपुर पुलिस की टीम के साथ मिलकर मौके पर घेराबंदी की। इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो लोग आते दिखे, जिन्हे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान बदमाशों ने बाइक तेज कर दी और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में विशाल नामक बदमाश को पैर में गोली लग गई। इसके बाद वह नीचे गिर पड़ा। वहीं, उसका साथी रोहित पुलिस से बचने के लिए भागने लगा। इसके बाद एसओजी के जवानों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ की इस घटना में घायल हुए बदमाश विशाल के खिलाफ वाराणसी के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल, मूल रूप से बिहार के सासाराम जनपद के रहने वाले विनोद कुमार का शिवपुर में मकान है। बीते 1 जून को पूरा परिवार चाचा की तेरही में शामिल होने के लिए बिहार गया हुआ था। इसी दौरान उनके घर में रखें 1.90 लाख रुपए कैश, हीरे, सोने व चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे।